(सुखीराम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा

एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश।)

पूर्ण पीठ।

एस. एस. संधावालिया, सी.जे., पी. सी. जैन और एम. आर. शर्मा, जे.जे. के समक्ष

सुखीराम

बनाम

स्टेट ऑफ हरियाणा ।

नियमित द्वितीय अपील संख्या 1535/1974।

19 मार्च, 1982।

औद्योगिक विवाद अधिनियम (XIV का 1947) - धारा 2 (k), 2-A और 10 - सिविल प्रक्रिया संहिता (V का 1908) - धारा - सेवा से निकाले गए कर्मचारी - निकाले गए कर्मचारी द्वारा अधिनियम के तहत अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाना - विवाद उत्पन्न करना - फिर भी, बर्खास्तगी को एक सिविल कोर्ट में मुकदमे के माध्यम से चुनौती दी गई - ऐसा कोर्ट - क्या उस मुकदमे को सुनने का अधिकार है।

यह निर्धारित किया गया कि जहां दावा किये गए अधिकार या दायित्व का मूल स्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के भीतर होता है और किसी अन्य स्रोत से नहीं, तो इसके लिए उपचार भी उसी कानून के प्रक्रियात्मक प्रावधानों के भीतर ही होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई दावा धारा 25-बी, 25-सी, 25-एफ और 25-एफएफ या बी-जी (सब कुछ समाहित किये बिना) पर आधारित होता है, तो यह औद्योगिक विवाद संबंधित होगा अधिनियम के तहत निर्मित एक अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से। उपर्युक्त अधिकार और दायित्व विशेष रूप से कानून की उपज हैं। उदाहरण के लिए, यदि अधिनियम कानून की पुस्तक पर नहीं होता, तो उनके संदर्भ में कोई 'औद्योगिक विवाद' संभवत: उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसलिए, मुद्दे का मूल्यांकन करते समय पहली परीक्षा यह है कि क्या अधिनियम और केवल अधिनियम से उत्पन्न होने वाला अधिकार या दायित्व विवाद का कारण बनता है। यदि ऐसा है, तो उपलब्ध एकमात्र उपचार अधिनियम का सहारा लेना है और उसके द्वारा निर्धारित मंचों और प्रक्रियाओं का उपयोग करना है और सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अनुमानित रूप से निषेधित होगा। किंतु जहां औद्योगिक विवाद से उत्पन्न अधिकार या दायित्व अधिनियम के अलावा किसी अन्य स्रोत से आता है - अर्थात्, सामान्य कानून के अंतर्गत (जिसमें किसी अन्य कानून को भी शामिल किया जाता है) - तब कर्मचारी को दो वैकल्पिक उपाय प्रदान किए जाते हैं। ऐसे

मामले में, उसे निर्णय लेने का अधिकार है कि वह या तो सिविल कोर्ट के सामान्य अधिकार क्षेत्र का उपयोग करे या अधिनियम के तहत उपचार की मांग करे। हालांकि, उसे अपने उपचार को स्पष्ट रूप से प्रभावित करना होगा और वह दोनों नहीं पा सकता। उसे एक या दूसरे का चुनाव करना होगा। इस प्रकार, जहां किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी या हटाने से उत्पन्न विवाद सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकारों या दायित्वों से जुड़ा होता है और कर्मचारी ने अधिनियम के तहत किसी भी उपाय का सहारा नहीं लिया है, अर्थात्, किसी औद्योगिक विवाद को उठाने का प्रयास नहीं किया गया था न ही अधिनियम की धारा 10 के तहत किसी संदर्भ का दावा किया गया था, तो कर्मचारी को उसके लिए उपलब्ध दो वैकल्पिक उपचारों में से एक का चुनाव करने का अधिकार होगा। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि सिविल कोर्ट को उस औद्योगिक विवाद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है जो सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है, यदि कर्मचारी ने पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपचार का सहारा नहीं लिया हो। (पैराग्राफ 8, 10, 11 और 14)।

"बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1980 (1) एस.एल.आर.

निरस्त।

यह मामला माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा द्वारा 27 जनवरी, 1981 को एक पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया था, ताकि इस मामले में शामिल महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों का निर्णय किया जा सके। पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस. एस. संधावालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. सी. जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा शामिल थे। इस पीठ ने संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के बाद, 19 मार्च, 1982 को मामले को फिर से एक एकल न्यायाधीश को योग्यता के आधार पर निपटाने के लिए संदर्भित किया...

नियमित द्वितीय अपील श्री आर. एस. गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रोहतक के 22 फरवरी 1974 के आदेश से, जिसने श्री एस. एन. चड्ढा, उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी रोहतक के 8 जून, 1973 के आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें वादी का मुकदमा खारिज किया गया था।

धारा 5 के तहत सीमा अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन, याचिका करता है कि देरी को माफ किया जाए, ताकि वादी-अपीलकर्ता को अपूरणीय हानि न हो।"

रवि नंदा, अधिवक्ता श्री जे. एम. सेठी, अधिवक्ता और श्री एस. एस. महाजन, अधिवक्ता के साथ, याचिकाकर्ता के लिए,

के. पी. भंडारी, अधिवक्ता श्री रवि कपूर, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश।

1. पूर्ण पीठ द्वारा इस बारह नियमित द्वितीय अपीलों के सेट में विचारणीय महत्वपूर्ण प्रश्न को निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ आदेश में इस प्रकार निर्मित किया गया है:–
   'क्या एक सिविल कोर्ट को उस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है जो एक श्रमिक द्वारा दायर किया गया है, जो एक राज्य विभाग उपक्रम में नियोजित है, जिसकी सेवा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा संरक्षित है, और जिसने विवाद को श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल के समक्ष भेजने के लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई कदम नहीं उठाया है।'"
2. सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने सहमति जताई है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सटीक मुद्दे के लिमिटेड उद्देश्य के लिए, अनुच्छेद 311 के संरक्षण वाले श्रमिक और इस प्रकार से संरक्षित न होने वाले श्रमिक के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। यह सामान्य मामला है कि प्रश्न का उत्तर श्रमिकों के लिए लागू होगा, चाहे उपरोक्त वर्गीकरण के बावजूद। अतः, प्रश्न की परिधि को इसके अनुसार बढ़ाते हुए, हम प्रश्न को इस प्रकार पुनः परिभाषित करेंगे: –
   'क्या सिविल कोर्ट को औद्योगिक विवाद से संबंधित एक श्रमिक द्वारा दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है, अगर पहले उस द्वारा इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल को संदर्भित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया हो।'

मुद्दा मुख्य रूप से कानूनी होने के कारण, तथ्य सापेक्षिक रूप से महत्वहीन हो जाते हैं। फिर भी, प्रश्न को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का संक्षेप में उल्लेख करना होगा और आर.एस.ए. संख्या 1535 के 1974 में उन्हें नोटिस करना पर्याप्त है।"

3. सुखी राम, अपीलकर्ता, जून 1971 में हरियाणा रोडवेज में 'अस्थायी आधार पर' बस कंडक्टर के रूप में कार्यरत थे। उनके द्वारा एकत्रित किए गए बस किराए के गबन के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, जो हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक द्वारा 25 अगस्त, 1971 को दिए गए उनकी सेवाओं के समापन के आदेश में समाप्त हुई। इसके बाद उन्होंने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें

घोषणात्मक डिक्री की मांग की गई थी कि उपरोक्त आदेश अवैध, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था और उन्होंने हरियाणा रोडवेज के बस कंडक्टर के रूप में सेवा में जारी रहने के घोषणा की मांग की। प्रतिवादी-राज्य ने मुकदमे का विरोध किया और महत्वपूर्ण मुद्दा संख्या 1 निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया: –

"क्या 25 अगस्त, 1971 को जारी किया गया विवादित समापन आदेश अमान्य, अवैध, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जैसा कि पैरा 9 के उप-पैराग्राफ 1 से 3 में उल्लिखित है और वाद में बताया गया है?" प्राथमिक न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णय दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक ने प्राथमिक न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा और 22 फरवरी, 1974 को उसे खारिज कर दिया।

4. उपरोक्त निर्णयों के खिलाफ नियमित द्वितीय अपील, साथ ही अन्य संबंधित अपीलें, जिनमें राज्य द्वारा पसंदीदा अपीलें भी शामिल थीं, पहली बार मेरे विद्वान भाई शैमा जे. के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। वहां राज्य की ओर से दृढ़ता से तर्क दिया गया कि चूंकि वादी-अपीलकर्ता उचित सरकार के रोडवेज विभाग द्वारा नियुक्त किए गए थे, इसलिए उनकी बर्खास्तगी या सेवा से हटाने से औद्योगिक विवाद का निर्माण होता है, जो केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित था और, इसलिए, सिविल कोर्ट की संज्ञान के बाहर था। इस तर्क के लिए मुख्य रूप से **बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1], में डिवीजन बेंच के निर्णय पर निर्भरता की गई थी और उसी तरह **पंजाब राज्य बनाम द्वारका दास**[2] के मामले में संदर्भ दिया गया था।

   उपरोक्त दोनों मामलों में, श्रमिकों ने राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 10 के तहत 'संदर्भ' बनाने के लिए संपर्क नहीं किया था, फिर भी यह निर्धारित किया गया था कि सिविल कोर्ट का मामले की संज्ञान लेने का अधिकार निहित रूप से वर्जित था। सिद्धांत और न्यायिक मत में कुछ विरोधाभास को देखते हुए और मुद्दे के स्पष्ट महत्व के मद्देनजर, इसे पूर्ण पीठ के समक्ष निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था।

---

[1] 1980 (1)

[2] 1976 P.L.R.92

5. वापस हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रश्न पर आते हुए, सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि औद्योगिक विवादों के संबंध में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्जित करने वाला अधिनियम में कोई विशिष्ट धारा नहीं है। इसलिए, इस मुद्दे की जांच उस बड़े सिद्धांत के आधार पर की जानी है कि यदि किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या न्यायाधिकरण का सृजन किया जाता है, तो ऐसे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामले, सिविल कोर्ट की संज्ञान से निहित रूप से वर्जित होते हैं। हालांकि यह प्रस्तावना स्थापित है, फिर भी इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसा कि इस बिंदु पर पहले के न्यायिक पूर्वनिर्णयों के संघर्ष से स्पष्ट है। सौभाग्य से, हालांकि, अधिनियम के विशिष्ट संदर्भ में, मामला अंतिम न्यायालय के बाध्यकारी पूर्वनिर्णय के कैनवास के भीतर एक संकीर्ण परिधि में सीमित हो गया है। **द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कामतकर शांताराम कडके और अन्य,**[3] में, उनकी लॉर्डशिप ने इस मुद्दे को सिद्धांत और पूर्वनिर्णयों के व्यापक कैनवास के खिलाफ जांचा और चार संक्षिप्त सिद्धांतों में कानून का सारांश दिया। इसलिए, इस अधिकार क्षेत्र के भीतर, अब प्राधिकारित रूप से निर्धारित सिद्धांतों से परे जाने की आवश्यकता नहीं है। चार सिद्धांत, जो अब लागू होते हैं, रिपोर्ट के पैराग्राफ 23 में इस प्रकार हैं:–

> (1) यदि विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है, न ही यह अधिनियम के तहत किसी अन्य अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, तो उपाय केवल सिविल कोर्ट में ही है।
>
> (2) यदि विवाद औद्योगिक विवाद है जो सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है और अधिनियम के तहत नहीं, तो सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक है, जिससे संबंधित वादी को उसके लिए उपयुक्त उपाय चुनने का विकल्प दिया जाता है।
>
> (3) यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित है, तो वादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अधिनियम के तहत निर्णय प्राप्त करना है।
>
> (4) यदि प्रवर्तन के लिए चाहा जा रहा अधिकार अधिनियम के तहत बनाया गया अधिकार है, जैसे कि अध्याय V-A, तो उसके प्रवर्तन के लिए उपाय या तो धारा 33-C है या औद्योगिक विवाद का उठाना है, जैसा कि मामला हो सकता है।"

---

[3] 1975 SC 2238

6. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता पूरी तरह से सहमत हैं (और यह अन्यथा समान रूप से स्पष्ट प्रतीत होता है) कि यहाँ पर विचारणीय मुद्दा ऊपर वर्णित सिद्धांत (2) के सही अनुप्रयोग का है। यह सामान्य मामला है कि राज्य रोडवेज विभागों में नियोजित श्रमिकों की बर्खास्तगी या हटाने से उनके अधीन सामान्य या सामान्य कानून के तहत अर्जित अधिकारों या दायित्वों से उत्पन्न होने वाले विवाद का निर्माण होता है। यहाँ तक कि यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम बिल्कुल भी कानूनी पुस्तक पर न हो, तो भी श्रमिक अपनी बर्खास्तगी या हटाने के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए सिविल अदालतों में अपने सामान्य सिविल अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार, यहाँ प्रयुक्त अधिकारों या दायित्वों के संबंध में कोई संदेह नहीं है कि ये केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम की ही सृष्टि नहीं हैं, बल्कि वास्तव में इससे बाहर मौजूद हैं।
7. उपरोक्त सहमति वाले प्रतिज्ञान पर, अब हम 'द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड' मामले (उपर्युक्त) में निर्धारित सिद्धांत (2) के सही अनुप्रयोग पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने से पहले, अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की पृष्ठभूमि रखना आवश्यक है। अधिनियम का बड़ा उद्देश्य, जैसा कि इसके प्रस्तावना से स्पष्ट होता है, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए प्रावधान करना है, जिसमें उनके निर्णय भी शामिल हैं। अधिनियम में मूल रूप से कल्पना की गई थी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग संविदा श्रमिकों के संघ के प्रतिनिधित्व और प्रबंधन के बीच हो - एक मामला जो सामान्य कानून या संविदा कानून के क्षेत्र से बाहर था। 'औद्योगिक विवाद' की अभिव्यक्ति को अधिनियम की धारा 2 (k) में निम्नलिखित रूप में व्यापक रूप से परिभाषित किया गया था: –

> 'औद्योगिक विवाद' का अर्थ है किसी भी कर्मचारी और नियोक्ता के बीच, या नियोक्ताओं और कामगारों के बीच, या कामगारों और कामगारों के बीच का कोई विवाद या मतभेद, जो किसी व्यक्ति के रोजगार या बेरोजगारी या रोजगार की शर्तों या श्रम की स्थितियों से संबंधित है।
>
> उपर्युक्त परिभाषा और निर्माण के आधार पर, यह आक्षरिक था कि व्यक्तिगत विवाद अधिनियम के दायरे में नहीं थे जब तक कि इन्हें श्रमिकों के एक संघ द्वारा प्रायोजित या अपनाया नहीं गया था। इस स्थिति को ठीक करने के लिए, अधिनियम संख्या 35 के 1965 द्वारा, धारा 2-ए (जो निम्नलिखित शर्तों में है) को कानून में डाला गया था: –

"4-ए एक व्यक्तिगत श्रमिक की बर्खास्तगी, आदि को औद्योगिक विवाद माना जाएगा–जहां कोई नियोक्ता किसी व्यक्तिगत श्रमिक की सेवाओं को निरस्त करता है, बर्खास्त करता है, छंटनी करता है या अन्यथा समाप्त करता है, उस श्रमिक और उसके नियोक्ता के बीच ऐसी निरस्ती, बर्खास्ती, छंटनी या समाप्ति से संबंधित या उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या अंतर औद्योगिक विवाद माना जाएगा, भले ही कोई अन्य श्रमिक या श्रमिकों का कोई संघ विवाद का पक्ष न हो।"

तो, औद्योगिक विवादों के संदर्भ या न्यायाधिकरणों के लिए धारा 10 के प्रासंगिक भाग पर ध्यान देने की जरूरत है: –

(1) जहां उचित सरकार का मत है कि कोई औद्योगिक विवाद है या उसकी संभावना है, वह कभी भी, लिखित आदेश द्वारा–

a. विवाद को उसके निपटान के लिए एक बोर्ड को संदर्भित कर सकती है, या
b. विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले किसी भी मामले को जांच के लिए एक अदालत को संदर्भित कर सकती है; या
c. विवाद या विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले, किसी भी मामले को, यदि यह द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित है, तो एक श्रम न्यायालय को निर्णय के लिए संदर्भित कर सकती है; या
d. विवाद या विवाद से संबंधित या प्रासंगिक प्रतीत होने वाले, चाहे यह द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित हो, तो एक ट्रिब्यूनल को निर्णय के लिए संदर्भित कर सकती है;

यह अब अनेक पूर्वनिर्णयों द्वारा स्थापित है कि अधिनियम के तहत औद्योगिक विवादों का निर्णय करने वाले अधिकारियों की शक्तियां सिविल कोर्ट की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत होती हैं, जबकि विवाद का निर्णय किया जाता है, जो एक औद्योगिक विवाद भी हो सकता है। श्रम न्यायालय और ट्रिब्यूनल, जिन्हें अधिनियम की धारा 10 के तहत सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, औद्योगिक शांति के लिए औद्योगिक नीति निर्धारित कर सकते हैं, वास्तव में नई संविदाएं बना सकते हैं,

और बर्खास्त श्रमिकों की पुनः नियुक्ति का आदेश दे सकते हैं, जो सामान्यतया एक सिविल कोर्ट नहीं कर सकता था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम एक श्रमिक को बहुत मूल्यवान अधिकार और उपाय प्रदान करता है जो अन्यथा उसे सामान्य या सामान्य कानून के तहत उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर भी, इनमें से कुछ अधिकारों और उपायों का लाभ उठाना धारा 1.0 के प्रावधानों और सरकार की विशेष मामले में संदर्भ को मना करने की शक्ति के अधीन है। इसी प्रावधान के कारण मुख्य रूप से, द प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मामले (उपर्युक्त) में उनकी लॉर्डशिप के समक्ष यह दृढ़ता से उर्जित किया गया था कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपाय कानून की नजर में कोई उपाय नहीं हैं और यह एक गलत नाम है। इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए, उनकी लॉर्डशिप ने इस प्रकार टिप्पणी की: –

> "हमें इन तर्कों में बहुत बल नहीं मिलता है। यह निस्संदेह सच है कि अधिनियम के तहत धारा 33-सी के तहत प्रदान किया गया उपाय, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो प्रबंधन और श्रमिकों के बीच पहुंचे गए दो समझौतों से संबंधित विवादों को लेकर है, उचित उपाय नहीं था। यह भी सच है कि श्रमिकों के लिए विवाद के निर्णय के लिए सीधे श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल के पास जाना संभव नहीं था। यह आगे इस न्यायालय के प्राधिकारों पर अच्छी तरह से स्थापित है कि सरकार कुछ परिस्थितियों में यहाँ तक कि उपयोगिता के आधार पर (देखें **राज्य बॉम्बे बनाम के. पी. कृष्णन,** और) **बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स बनाम राज्य बॉम्बे,**[4] संदर्भ बनाने से इनकार कर सकती है। यदि इनकार कानूनी रूप से स्थायी नहीं होता है, तो उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उचित निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन इस सब से यह नहीं निकलता है कि अधिनियम के तहत प्रदान किया गया उपाय एक गलत नाम है। औद्योगिक विवादों का धारा 10 (1) के तहत सरकार की शक्ति के प्रयोग में निर्णय के लिए संदर्भित करना इतना आम है कि इसे उपचार के रूप में गलत नाम या अपर्याप्त या अनुपयुक्त कहना मुश्किल है, अधिनियम के तहत निर्मित अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए। इस उपचार में कुछ बाधाएं हैं लेकिन श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल की व्यापक शक्तियों के निर्माण से यह अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति हो जाती है। यह बाधा

[4] AIR 1963 S.C.1617

केवल इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि सामान्य या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व के संबंध में और अधिनियम के तहत निर्मित नहीं होने पर एक औद्योगिक विवाद के निर्णय के लिए उपचार विशेष नहीं है। यह एक विकल्प है। लेकिन निश्चित रूप से अधिनियम के तहत एक अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन के लिए इसमें उपलब्ध उपचार विशेष उपचार है। विधायका ने अपनी बुद्धि में इसे उचित नहीं समझा कि अधिनियम के तहत निर्मित अधिकारों और दायित्वों के प्रवर्तन के लिए एक बहुत आसान और सुगम उपचार प्रदान करे। ऐसे अधिकारों का आनंद लेने और इसके प्रवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए उपचार से संतुष्ट रहना चाहिए। इस बात की संभावना कि सरकार अंततः धारा 10 के तहत एक औद्योगिक विवाद का संदर्भित नहीं कर सकती है, व्यवहार्यता के आधार पर, इस संबंध में एक प्रासंगिक विचार नहीं है?

उपर्युक्त विचार के अनुरूप, यह निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले में, यह कहने के बावजूद कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाधित करने के लिए कोई विशिष्ट धारा नहीं थी, फिर भी सिद्धांत (3) और (4) के तहत, सामान्य सिद्धांतों पर नागरिक न्यायालयों की ओर रुख करना अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध होगा।

8. अब मंच तैयार है प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले में उनकी लॉर्डशिप द्वारा घोषित सिद्धांत (2) के सच्चे अनुप्रयोग के लिए। सिद्धांत (2), (3) और (4) के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें दो अलग और स्वतंत्र क्षेत्र देखे जा सकते हैं। पहला, जहां दावा किया गया अधिकार या दायित्व का स्रोत औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर ही होता है और कहीं और से नहीं। यह अपने आप में एक विशिष्ट वर्ग बनाता है। इस क्षेत्र के लिए, अब यह आधिकारिक रूप से तय है कि अगर अधिकार या दायित्व अधिनियम से ही आता है, तो उसके लिए उपचार भी उसी अधिनियम के प्रक्रियात्मक प्रावधानों के भीतर ही होगा। सिद्धांत (3) और (4) इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 'दावा धारा 25-बी, 25-सी, 25-एफ और 25-एफएफ या 25-जी (बिना सीमाबद्ध हो) पर आधारित है, तो यह अधिनियम के तहत निर्मित एक अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित औद्योगिक विवाद होगा। उपर्युक्त अधिकार और दायित्व विशेष रूप से केवल अधिनियम के द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अधिनियम कानूनी पुस्तक पर नहीं होता, तो उनके संदर्भ

में कोई भी 'औद्योगिक विवाद' संभवतः उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसलिए, मुद्दे का मूल्यांकन करते समय पहला परीक्षण यह है– क्या अधिकार या दायित्व जो विवाद को जन्म देता है, वह अधिनियम से और केवल अधिनियम से आता है। यदि ऐसा है, तो उपलब्ध एकमात्र उपचार यह है कि अधिनियम का सहारा लिया जाए और उसके द्वारा निर्धारित रूपों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। सिद्धांत (3) और (4) के दृष्टिकोण से, सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध हो जाएगा।

9. हालांकि उपरोक्त मुद्दा सिद्धांत पर स्पष्ट प्रतीत होता है, इस अदालत के भीतर का पूर्ववर्ती अभ्यास भी इसके साथ समान रूप से संगत है। सबसे पहले द्वारका दास के मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। उसमें, जिस अधिकार का आह्वान किया गया था वह अधिनियम की धारा 26-एफ (2) (ए) (द्वितीय) के तहत था और तदनुसार सीधे अधिनियम से उत्पन्न हुआ था। सीखे हुए सिंगल जज ने माना कि ऐसे मामले में सिविल मुकदमे के रूप में उपचार के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष बाधा थी, भले ही प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले में निर्णय का संदर्भ न दिया गया हो, जो बेंच के संज्ञान में नहीं लाया गया था। अपील पर, लेटर्स पेटेंट बेंच ने (द्वारका दास बनाम पंजाब राज्य) मामले में, (6) ने फैसले को स्पष्ट रूप से मान्य करते हुए यह माना कि मामला प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले के सिद्धांत (3) के भीतर आता है। द्वारका दास के मामले में दृष्टिकोण की सहीता के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा कोई चुनौती नहीं उठाई गई थी, और हम अन्यथा उसी से सहमत हैं और इसलिए, बिना संकोच के उस दृष्टिकोण को मान्य करेंगे।

10. अब दूसरी विशिष्ट श्रेणी की ओर बढ़ते हुए, जहाँ औद्योगिक विवाद को जन्म देने वाला अधिकार या दायित्व अधिनियम के अलावा किसी अन्य स्रोत से आता है - अर्थात्, सामान्य कानून के अंतर्गत (इसमें किसी अन्य अधिनियमों को भी शामिल करते हुए) तब सिद्धांत (2) के अनुसार, कामगार को स्पष्ट रूप से दो विकल्पीय उपचार दिए जाते हैं। ऐसे मामले में, उसे या तो सिविल न्यायालयों के सामान्य अधिकार क्षेत्र का सहारा लेने का विकल्प होता है या अधिनियम के तहत उपचार की मांग करने का। हालांकि, उसे अपने उपचार का निर्वाचन स्पष्ट रूप से करना चाहिए। अब यह आधिकारिक रूप से स्थापित है कि वह दोनों नहीं चुन सकता है। उसे एक या दूसरे का चयन करना होता है।

11. वर्तमान मामले में, जैसा कि पैराग्राफ-6 में पहले ही देखा गया है, यह सामान्य मामला है कि कामगारों की बर्खास्तगी या निकाले जाने से उत्पन्न विवाद सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकारों या दायित्वों से संबंधित है। एक बार यह स्थापित हो जाने पर, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले का सिद्धांत (2) तुरंत आकर्षित हो जाता है और कामगारों को उनके लिए उपलब्ध दोनों वैकल्पिक उपचारों में से एक को चुनने का अधिकार होता है। यहां कोई विवाद नहीं है कि कामगारों ने अधिनियम के तहत किसी भी उपचार का सहारा नहीं लिया है। उनकी ओर से कोई औद्योगिक विवाद उठाने की कोशिश नहीं की गई थी और न ही अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई संदर्भ दावा किया गया था। उन्होंने सीधे अपना चुनाव किया और नागरिक न्यायालयों में अपने अधिकारों को उठाने का फैसला किया। इसलिए, सिद्धांत और बाध्यकारी पूर्वनिर्णय के आधार पर, वे स्पष्ट रूप से नागरिक मुकदमे के माध्यम से राहत का दावा करने के हकदार होंगे।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रति न्याय के लिए, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहस के दौरान **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम दर्शन कुमार जिंदल** मामले में डिवीजन बेंच के निर्णय का संदर्भ दिया गया था,। इसकी सहीता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि केवल संदर्भ मांगने को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एक उपचार चुनने के रूप में नहीं माना जाएगा और उपरोक्त निर्णय के पैरा-10 में किए गए विचारों को पुनर्विचार की आवश्यकता है। हालांकि, मेरे विचार में इस प्रश्न पर विचार की आवश्यकता इस मामले में नहीं है क्योंकि यह हमारे निर्णय के लिए बिलकुल भी नहीं उठता है। निस्संदेह, बनारसी दास के मामले (उपरोक्त) में किए गए अवलोकनों के मद्देनजर एक असंगति का स्पर्श है। उस निर्णय में संदर्भ से पता चलता है कि अधिवक्ता प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले में सिद्धांत (2) की सूक्ष्मताओं को उजागर करने में लापरवाह रहे थे। वास्तव में; मामले पर पर्याप्त रूप से बहस ही नहीं की गई थी।

13. 13. निस्संदेह, बनारसी दास के मामले (उपरोक्त) में किए गए अवलोकनों के मद्देनजर एक असंगति का स्पर्श है। उस निर्णय का संदर्भ लेने से पता चलता है कि अधिवक्ता प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले में सिद्धांत (2) की सूक्ष्मताओं को उजागर करने में लापरवाह रहे थे। वास्तव में, इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से बहस ही नहीं की गई थी। द्वारका दास के मामले (उपरोक्त) में सीखे हुए सिंगल जज के पहले के विचार और उसकी पुष्टि लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा की गई थी, जिसे बेंच के संज्ञान में नहीं लाया

गया था। मुद्दे को ठीक से प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, डिवीजन बेंच ने बनारसी दास के मामले में केवल प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के रिपोर्ट में पैराग्राफ-24 पर भरोसा किया था, हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के दावे को नकारने के लिए, सिविल अदालत में उसके उपचार का पीछा करने के लिए। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के मामले में उपर्युक्त पैराग्राफ 24 को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि उनकी लॉर्डशिप ने खुद अधिनियम की धारा 2-ए के तहत आने वाले व्यक्तिगत औद्योगिक विवाद को ऐसा माना जिसमें सिविल अदालत का सहारा लेने की संभावना होगी। उन्होंने केवल यह अवलोकन किया था कि अधिनियम की धारा 2 (क) के अर्थ में औद्योगिक विवाद अधिकांशतः अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और इस प्रकार सिद्धांत (3) द्वारा नियंत्रित होंगे। यदि सिद्धांत (2) को इतना शाब्दिक रूप से समझा जाए, तो उससे प्रस्तुत वैकल्पिक उपचार प्रायः निरर्थक बन जाएगा। सबसे बड़े सम्मान के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि बनारसी दास के मामले में व्यक्त किया गया विचार अत्यधिक सीमित है और कानून को सही ढंग से स्थापित नहीं करता है, और इसलिए, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

14. उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में, हम प्रश्न का उत्तर (जैसा कि पैराग्राफ 2 में ऊपर पुनः रूपांतरित किया गया है) सकारात्मक रूप में देंगे। यह माना जाता है कि सिविल न्यायालय को एक कामगार द्वारा एक मुकदमा सुनने का अधिकार है, जो औद्योगिक विवाद के संबंध में हो, जो सामान्य या सामान्य कानून के तहत अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है (और अधिनियम के तहत नहीं), यदि उसने पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उपचार का सहारा नहीं लिया होता;

15. इन सभी अपीलों को अब उपर्युक्त कानूनी प्रश्न के उत्तर के प्रकाश में योग्यता पर निपटाने के लिए सीखे हुए सिंगल जज के पास वापस भेजा जाएगा।

प्रेम चंद जैन, जे.– मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा

(सुखीराम बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा

एस. एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश।)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा